Title: Regarding disinvestments of Government Shares in HPCL and BPCL.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, you have agreed to allow a discussion on the disinvestment of the profit making oil majors like HPCL and BPCL. But what I want to add is that the workers and employees, including the top management, are opposing disinvestment irrespective of any political affiliations.

All the Trade Unions are united to oppose the decision of this Government. So, the Government should not make any further progress in the matter. They should not proceed at all till a final decision is taken by this Parliament, because nationalisation took place by an Act of Parliament. Whatever the interpretation of others, this House cannot be taken for granted. The right of this sovereign august body cannot be allowed to be diluted in such a manner. The Executive is accountable. There is no consensus in the Government. There is no consensus among the partners of the Government. In such a situation, the Government should not proceed even a single step before a final decision is taken by this Parliament. Since you have already assured, I am not elaborating the issue. But corruption is taking place. Private monopoly is going to stay after disinvestment. All these are major issues. The Government should not proceed any further before a final decision is taken by this Parliament. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are also allowed to associate with this issue.

...(*Interruptions*)

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : The Attorney-General is not an authority. The Attorney-General can give his opinion and we can differ.â€¦ (*Interruptions*)

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, हम इस बात का समर्थन करते हैं। हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध किया है, वहां के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। कर्मचारियों की भावना को ध्यान में रखना चाहिए, वे स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। यहां बसुदेव आचार्य जी ने यह मामला उठाया था।â€¦ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : हम लोग इनकी बात का पूरा समर्थन करते हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मेरे कहने का कोई असर इस सरकार के ऊपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। न केवल विरोध पक्ष के लोग, बल्कि सरकारी पक्ष के लोग भी इस राय के हैं कि इस तरह से हमारे उद्योगों को नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इसे राट्रीय सम्मान की बात बना रखा है। मुझे नहीं मालूम कि उसे बेचकर ये क्या पाने वाले हैं, सिवा इसके कि कुछ बहुराट्रीय कम्पनियों को और कुछ इस देश की बड़ी कम्पनियों को खुश करना चाहते हैं। इससे न मजदूरों का भला है, न किसानों का भला है, न उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का भला है। भला केवल चन्द लोगों का होने वाला है और सरकार इस तरह बात कर रही है, जैसे राट्रीय सम्मान के लिए यह काम जरूरी है। इन्होंने कहा था कि हम 12 हजार करोड़ रुपये इकट्ठा करेंगे। तीन हजार करोड़ रुपये अब तक इकट्ठे हुए हैं। अगले पांच वर्षों में, 10 वर्षों में या कितने वर्षों में 70 हजार करोड़ रुपये की मिल्कियत ये बेचना चाहते हैं। सरकार को कभी यह भी हिसाब देना चाहिए कि अगर यही उद्योग फिर से लगाने पड़े तो क्या 70 हजार करोड़ रुपये में लगा सकते हैं। अगर खाद के कारखाने बेच दिये गये, मान लीजिए कि दूसरे देश खाद देना बन्द कर दें तो हमारी हरित क्रान्ति का क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा। हमारे तेल के कारखानों को ये बेचने जा रहे हैं, हमारे जितने एयरपोर्ट्स हैं, उनको बेचने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इसमें एक राय रही है, मैं आपकी राय नहीं देना चाहता, लेकिन अगर इस सरकार के ऊपर कोई नैतिक असर आप डाल सकें और खास तौर से उनके ऊपर, जो इस देश के लिए जिम्मेदार हैं, तो देश के भविय के लिए यह एक अच्छी बात होगी।

MR. SPEAKER: Shri Jaipal Reddy, I think you want to speak on the same issue.

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Yes, Sir.

Sir, I completely endorse the views expressed by Shri Chandra Shekhar. I think it is not merely a legalistic question. What opinion has been given by the Attorney General can at best be termed as legalistic though some of us doubt the legal validity of the advice given by the Attorney-General because many senior advocates in the country have questioned the legal reasoning behind the advice given by the Attorney-General. Therefore, we have the considered view that the Attorney-General could be requested to come to the House to explain to us as to what was the basis for the opinion he tendered to the Government.

Quite apart from the legalistic implications, there are substantive issues. The HPCL and the BPCL have been built at a huge cost over the decades. It is very easy for you to dismantle them and sell them off as part of a distress sale. I do not think the Government should rush in like fools where angels fear to tread. Therefore, we are of the view that this issue should not only be discussed in the House but the Government should also not take it as a prestige issue. The Government should in fact review the entire process. We are for disinvestment in areas that are not strategic and in regard to PSUs incurring losses. ...(*Interruptions*)

SHRI KIRIT SOMAIYA : Sir, we have discussed this in the Question Hour and you have also promised a full-fledged debate. So, why should we start discussing the whole issue again? ...(*Interruptions*)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही बात कहनी है कि मंत्रिपरिद के कुछ सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया था। अब किस परिस्थिति में उन्होंने इसका समर्थन किया, यह उनको इस सदन में आकर एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या वे अपना स्थान मंत्रिमंडल में गंवाना नहीं चाहते या और कोई कारण है ? â€¦ (व्यवधान)किस कारण से उन्होंने इसका समर्थन किया, यह भी वे स्पट करें। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि श्री किरीट सौमेया जी ने अभी कहा कि क्वश्चन ऑवर में इस विाय पर 40 मिनट तक चर्चा हुई है। श्री चन्द्रशेखर जी इस विाय पर बोलना चाहते थे तो मैंने उनको बोलने की इजाजत दी। इसी तरह श्री जयपाल रेड्डी को भी मैंने बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं इस विाय को चर्चा के लिए ओपन नहीं कर सकता। वैसे भी इस विाय पर चर्चा होने वाली है। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसे एग्री करेगी तब चर्चा होगी। उस समय आप बोल सकते हैं। अभी मैं किसी को भी इस विाय पर बोलने के लिए इजाजत नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)